पूर्वांचल-बुंदेलखंड की विकास योजनाएं बनाएगी मंत्रिपरिषद की उप समिति

महेंद्र तिवारी

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में उप समिति गठित, तीन महीने में रिपोर्ट मांगी, 30 माह में करना होगा क्रियान्वयन, वित्त विभाग को बजट व्यवस्था के निर्देश

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल व बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए आई संस्तुतियों पर निर्णय कर विभागीय कार्ययोजना तैयार करने के लिए मंत्रिपरिषद की उप समिति का गठन किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में गठित उप समिति से तीन माह में रिपोर्ट मांगी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में शुमार पूर्वांचल व बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए विचार-विमर्श कर संस्तुति देने को कहा था। इसके लिए नियोजन विभाग ने दोनों क्षेत्रों में सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए। इसमें बड़ी संख्या में विशेषज्ञ, शासन के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण संस्तुतियां दी थीं। इसके बाद सीएम ने इन संस्तुतियों के आधार पर कार्ययोजना तैयार कराने व समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन का निर्देश दिया था।

अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने इन संस्तुतियों पर विचार कर विभागीय कार्ययोजना तैयार करने और उसके समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद की उपसमिति का गठन कर दिया है। कार्ययोजना के क्रियान्वयन की समयसीमा 30 महीने तय की गई है। गोयल ने कहा है मंत्रिपरिषद की उप समिति की बैठकों का आयोजन व विभागीय समन्वय का काम नियोजन विभाग करेगा। कार्ययोजना के लिए आवश्यक बजट का बंदोबस्त वित्त विभाग करेगा।

मंत्रिपरिषद की उप समिति में ये शामिल

- **अध्यक्ष :** सुरेश कुमार खन्ना, मंत्री वित्त, संसदीय कार्य व चिकित्सा शिक्षा
- **सदस्य :** सूर्य प्रताप शाही, मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा व कृषि अनुसंधान
- जय प्रताप सिंह, मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण
- राजेंद्र प्रताप सिंह (मोती सिंह), मंत्री ग्राम्य विकास व समग्र ग्राम विकास
- सिद्धार्थ नाथ सिंह, मंत्री खाद एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन एनआरआई व निवेश प्रोत्साहन
- महेंद्र सिंह, जल शक्ति मंत्री
- चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, राज्यमंत्री लोक निर्माण
- विशेष आमंत्रित सदस्य : केवी राजू आर्थिक सलाहकार मुख्यमंत्री
- सदस्य सचिव : कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव नियोजन

इन बिंदुओं के आधार पर कार्ययोजना बनाएगी उप समिति

- मातृ एवं शिशु से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य संकेतांकों में सुधार।
- साक्षरता की दर को शत-प्रतिशत कराकर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार।
- युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण।
- कृषि व कृषि उत्पादन से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति की आय में सुधार।
- महिला सहायता समूह का गठन। माइक्रो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराना।